कौन है भारतीय?

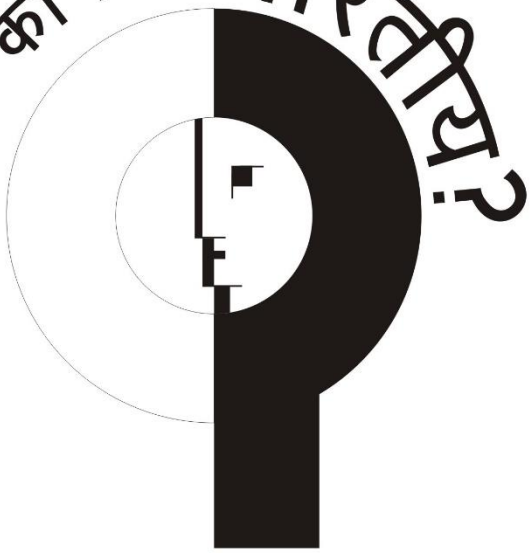

क्या कानून और संविधान से तय होगा?

cjp.org.in

विस्तृत जानकारी के लिए

cjpindia@gmail.com पर ईमेल करें

या हमारी वेबसाइट (cjp.org.in) पर संपर्क/विजिट करें।

प्रशिक्षण, बैठक और प्रशिक्षण सामग्री के लिए भी

(https://cjp.org.in/volunteer/) लिंक पर हमसे संपर्क करें।

इस पुस्तिका का कोई अंश या पूरी पुस्तिका पुन: प्रकाशन अनुमति के लिए कृपया
cjpindia@gmail.com पर ईमेल करें या 7506661171 नंबर पर व्हाट्सएप करें

प्रस्तावित अनुदान रु० 25/=

भारतीय कौन है, क्या कानून और संविधान से तय होगा?

NRC: एक संक्षिप्त इतिहास

नागरिकता का पूरा मुद्दा किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है और इसलिए इसे अधिकार पाने के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है।

नागरिकता (CITIZENSHIP) कई मायनों में व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध को परिभाषित करती है। भारत, जब स्वतंत्र (1947) हुआ और उसके बाद जब इसने खुद को एक समावेशी और समग्र राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता के आधार रेखांकित किए गए हैं), 1950 में स्वीकार किया कि सभी धर्मों, पंथों, जातियों, भाषाओं और लिंगों, के सभी लोग समान रूप से और बिना भेदभाव के भारतीय हैं।

पिछले छह वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर, इस संवैधानिक आधार को मौलिक रूप से बदल कर फिर से परिभाषित करने के लिए राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। पहला, प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक के साथ (जो कि 2016 में समाप्त हो गया था, लेकिन उसे फिर से संसद में 2019 के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना प्रस्तावित है) और दूसरा, जल्दबाजी में लाकर बिना ठीक से लागू किया गया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) प्रक्रिया। इसलिए, प्रत्येक भारतीय को यह जानना आवश्यक है कि ऐसे मुद्दे समाज में भारी उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर पहले से ही कई शहरों, राज्यों और क्षेत्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है; इसलिए इन मुद्दों की एक विस्तृत समझ रखना महत्वपूर्ण है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से के सात राज्यों में से एक असम पहले से ही इस प्रक्रिया से जूझ रहा है; 2013 के बाद तो इसे और भी ज़ोर शोर से लागू किया जा रहा है। असम के बाद अब पड़ोसी राज्य बंगाल में भी NRC लागू करने की अफवाहें आ रही हैं, असम में भाषाई और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हुए लोगों की दुर्दशा देखते हुए दहशत के कारण यहां केवल तीन महीनों में आत्महत्या और आघात की वजह से 11 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र ने मुंबई के बाहर एक डिटेंशन कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक ने न केवल एक डिटेंशन कैंप स्थापित करने की घोषणा की है, बल्कि "अवैध बांग्लादेशियों" के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) एक मानवाधिकार आंदोलन, जो अदालतों और उससे परे, हमारी मौलिक स्वतंत्रता को बनाए रखने और बचाव करने के लिए समर्पित है, 2017 के बाद से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिन रात काम कर रहा है। असम में हमारी 700 से अधिक वॉलंटियर्स की समर्पित टीम है। इन वॉलंटियर्स ने हजारों लोगों को एनआरसी प्रक्रिया को समझाने, फॉर्म भरने और इसे नेविगेट करने में मदद की है; बहिष्कृत किए गए लोगों को समझा बुझाकर उन्हें आत्महत्या करने से रोका है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स और उच्च न्यायालयों में उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का कानूनी रास्ता दिखाया है। (https://cjp.org.in/assam/)

अब, CJP ने पूरे भारत में काम करना शुरू कर दिया है। CJP अब देश के सभी राज्यों में मौजूदगी दर्शाते हुए जनसभा, कार्यकर्ताओं और कम्युनिटी लीडर्स की ट्रेनिंग के जरिए, देशव्यापी NRC और नागरिकता के प्रश्न के मुद्दे पर सामग्री वितरित कर रहा है। मुंबई, मालेगांव, बेंगलुरु, हैदराबाद,

कोलकाता, पुरी, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और दिल्ली में CJP की एनआरसी के बारे में जागरूकता के लिए बैठकें हुई हैं। CJP को आप जैसे लोगों की प्रतिबद्धता से बल मिलता है - जो हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं, और विशेष रूप से कमजोर और हाशिए के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं।

एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 6 सितंबर, 2019 को असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया है कि राज्य में NRC जैसी किसी भी प्रक्रिया को लागू नहीं होने दिया जाएगा। सदन के संचालन के नियम 185 के तहत पेश किए गए प्रस्ताव को तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों, विपक्षी दलों के ट्रेजरी बेंच के सदस्यों, वाम दलों के विधायकों और कांग्रेस का समर्थन मिला। केवल भाजपा के चंद सदस्यों ने प्रस्ताव का विरोध किया, मगर प्रस्ताव तीन घंटे की बहस के बाद पारित कर दिया गया।

असम में हुई एनआरसी प्रक्रिया के दौरान NRC का यातनापूर्ण अनुभव राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। जो कार्य अशांति और लाक्षियकरण से जूझते कई हितधारकों के बीच आपसी अनुमति के तहत शुरू हुआ था, वह गिरकर आज राजनैतिक और नौकरशाही का हथकंडा बन चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप 19 लाख से अधिक लोगों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया गया है।

पहले, दिसंबर 2017 में 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया था, फिर 31 जुलाई, 2018 तक 44 लाख लोग बाहर थे। हर दौर में, प्रत्येक व्यक्ति और परिवार इस निष्कासन के साये में रहा है। असम राज्य विधानसभा के पहले डिप्टी स्पीकर के परिवार के लोग, जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा की थी और युद्ध में दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, महिलाओं और बच्चों, यहाँ तक कि ऐसे भारतीय जिनके पास सभी दस्तावेज़ मौजूद हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। इन सभी को सरकार के 'लक्ष्यों को पूरा करने' के लिए कठिनाइयां उठानी पड़ीं और अवैध अप्रवासी नहीं होने के सबूत देने पड़े।

असम एनआरसी अपडेट प्रक्रिया से बहुत सारी व्यक्तिगत डरावनी कहानियां निकली हैं। असम के भीतर सबसे अधिक हाशिए वाले वर्गों के लिए मानवीय हानि और सामग्री की लागत बहुत मंहगी पड़ी है। आत्महत्या या आघात से (डिटेंशन कैंपों में) 100 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं जिसका अभिलेख सीजेपी ने किया है। नागरिकता से बाहर रखे गए लोगों का भाग्य असम के विदेशी ट्रिब्यूनलों (FTs) के भरोसे छोड़ दिया जाता है जिनका अपना ही रिकॉर्ड खराब और अनप्रोफेसनल है। यदि एक बार FT किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दे, तो उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जा सकता है। अब तक असम के छह डिटेंशन कैंपों में 27 मौतें हो चुकी हैं, जहां 2,000 से अधिक लोगों को नियमित कैदी को मिलने वाले अधिकारों के बिना क़ैद में रखा गया है। (https://www.youtube.com/watch?v=z5UeVs6hURM)

इन सभी आयामों को देखते हुए, जिनका किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वर्तमान में असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर को लागू किया जा रहा है और देश के अन्य भागों में विस्तारित होने की संभावना को एक राजनीतिक-कानूनी, ऐतिहासिक संदर्भ में इन सवालों का जवाब समझने की आवश्यकता है।

भाग एक: अखिल भारतीय और असम: नागरिकता क्या है?

भाग दो: असम: असम के लिए NRC अपडेशन प्रक्रिया का क्या अनुभव है, एकमात्र राज्य जिसने अभी तक इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया है?

भाग तीन: अखिल भारतीय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) क्या है, जिसे लागू करना अप्रैल 2020 से शुरू होगा और सितंबर 2020 में पूरा होगा?

भाग चार: अखिल भारतीय: नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर क्या है और इसका कानूनी आधार क्या है? भारतीयों के लिए एक राष्ट्रव्यापी NRC का क्या अर्थ है?

भाग पांच: प्रस्तावित कार्रवाई: क्या सभी पक्षों के भारतीयों को विपक्षी राजनीतिक दलों में शामिल होना चाहिए, एनपीआर की गणना के बाद पालन करने वाले पहलुओं पर स्पष्टता और चर्चा पर जोर नहीं देना चाहिए? क्या एनपीआर आवश्यक रूप से देशव्यापी एनआरसी का नेतृत्व करता है?

इन सवालों का जवाब यह पैंफलेट देने का प्रयास करेगी। पिछले तीन वर्षों में असम में इस संकट से निपटने में सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (cjp.org.in, cjpindia@gmail.com) सबसे आगे रहा है। इन गतिविधियों का विवरण इस पर्चे के अंत में दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में NRC को लेकर 'देशव्यापी' दहशत पैदा कर दी गई है। CJP को कोलकाता (बंगाल), मालेगाँव, भिवंडी (महाराष्ट्र), हैदराबाद (तेलंगाना) में सभाओं को संबोधित करने और नागरिकों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और राजनेताओं के "अवैध अप्रवासियों" को लेकर अनावश्यक रूप से आक्रामक बयान सामने आते रहते हैं, और यहां तक कि डिटेंशन कैंप स्थापित करने की बातें भी पारदर्शी नहीं रखी गईं हैं, इन्हें किसी चीज़ का उपाय तो कहा ही नहीं जा सकता है। इस पर्चे को इस विश्वास के साथ प्रकाशित किया जा रहा है कि कानूनी और संवैधानिक जागरूकता सभी मानव अधिकारों के मुद्दों के लिए आवश्यक है और नागरिकता उनमें से एक है। हम में से प्रत्येक को जानकारी से सुसज्जित होने और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है ताकि हम अपने मौलिक अधिकारों को लागू होने को लेकर तैयार रहें।

भाग एक: संपूर्ण भारत और असम:

नागरिकता क्या है?

नागरिकों के अधिकार: मतदान के अधिकारों के अलावा, नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गैर-भेदभाव, सभा आयोजन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि जैसे विभिन्न मौलिक अधिकारों के हक हैं। उन्हें स्थायी रूप से भारत में रहने का अधिकार है, जबकि विदेशियों को यह विशेषाधिकार नहीं है। नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, और लोकतांत्रिक राज्य की नीति नागरिकों के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अधिकांश राज्य कल्याणकारी योजनाएं केवल नागरिकों के लिए हैं।

विदेशी, केवल जीवन के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हक़दार हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन, 1951 और 1967 का प्रोटोकॉल शरणार्थियों को संरक्षण प्रदान करता है जिन्हें अपने देशों में प्रताड़ित किया गया हो, भारत इन दोनों में से एक में भी हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसके अलावा, भारत राजनीतिक शरण की अनुमति नहीं देता है। हालाँकि, भारत ने कुछ अपवादों को पहले, जैसे तिब्बतियों के मामले में विदेशी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र देने के माध्यम से किया था। सीधे शब्दों में कहें तो नागरिकता हमें अधिकार पाने का अधिकार देती है। भारत के संविधान के भाग II में नागरिकता को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 11 भविष्य के बारे में बताता है और संसद को नागरिकता से संबंधित कानूनों को लागू करने की अनुमति देता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के नागरिकता से संबंधित हैं।

संविधान लागू होने के समय यानी 26.1.1950 को नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 10 तक में बताया गया है। यहाँ मूल रूप से जन्म से नागरिकता होने की बात कही गई है, और प्रवास के विषय में कुछ प्रावधानों के साथ। लेकिन यह हमारे उद्देश्यों के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं है क्योंकि यह संविधान के लागू होने के समय के साथ जुड़े हैं। अनुच्छेद 11 भविष्य के बारे में बताता है और संसद को नागरिकता से संबंधित कानूनों को लागू करने की अनुमति देता है।

पूरे भारत में
नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं:

a) जन्म से
b) वंश द्वारा (भारतीय नागरिक माता-पिता से भारत के बाहर जन्म लेने वाले)
c) पंजीकरण द्वारा
d) प्राकृतिककरण द्वारा (बारह वर्षों तक भारत में मूल निवासी होने के कारण)
e) क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा (जैसे सिक्किम)

यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ है तो नागरिकता प्राप्त करने का प्रमुख तरीका प्राकृतिककरण या पंजीकरण के माध्यम से है। हालाँकि, ये दोनों तरीके 'अवैध प्रवासियों' के लिए उपलब्ध नहीं हैं। नागरिकता अधिनियम के तहत, एक अवैध प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया हो या वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज की तिथि बीतने के बाद भारत में रह गया हो (section 2(1)(b)). उदाहरण के लिए, एक बांग्लादेशी जिसने कथित तौर पर पासपोर्ट या वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया है, वह कभी भी भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है (कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि प्रवेश 25 मार्च 1971 से पहले असम में है) ।

जहां तक जन्म से नागरिकता का सवाल है, तो इनमे कई बार संशोधन किए गए हैं।

1987 से पहले: भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अपने आप में भारतीय नागरिकता का हकदार है, चाहे उस व्यक्ति के माता-पिता भले ही अवैध प्रवासी हों।

1987-2004: दिसंबर, 2004 के बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारतीय नागरिकता मिलेगी, बशर्ते कि उनके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हों, यानि माता-पिता दोनों में से कोई एक भी अवैध प्रवासी न हो।

2004 के बाद: इस प्रकार, 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए बच्चों को भारत में नागरिकता प्राप्त करने से रोका जाएगा यदि माता-पिता में से किसी एक को अवैध प्रवासी माना जाता है।

संक्षेप में, हममें से जो 1 जुलाई, 1987 से पहले पैदा हुए हैं, उनके लिए यह साबित करना पर्याप्त है कि हम भारत में पैदा होते ही नागरिकता पा गए थे। भारत में 1 जुलाई, 1987 और 3 दिसंबर, 2004 के बीच पैदा हुए लोगों के लिए, भारत में पैदा होना चाहिए और माता-पिता में से एक को बच्चे के जन्म के समय भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में 3 दिसंबर, 2004 के बाद पैदा हुए लोगों में से माता-पिता में से किसी एक को बच्चे के जन्म के समय न केवल भारत का नागरिक होना चाहिए, बल्कि माता पिता में से किसी को भी अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।

असम

1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में असम आंदोलन के कारण, अवैध प्रवासियों (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) IMDT Act, 1983 नामक एक अधिनियम पारित किया गया था। हालाँकि यह स्वचालित रूप से असम में लागू होता है। यदि केंद्र सरकार चाहती तो इसे भारत के अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जा सकता था, परन्तु ऐसा कभी नहीं किया गया। इस अधिनियम के तहत 25 मार्च, 1971 के बाद बिना पासपोर्ट या बिना अन्य वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करने वाले को अवैध प्रवासी के रूप में माना गया। इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी थी। प्रमुख मुद्दों में से एक यह था कि इस कानून के तहत सबूत पेश करने का बोझ कथित विदेशी पर नहीं था।

IMDT Act ख़ारिज कर दिया गया: इस अधिनियम को सर्बानंद सोनोवाल (जो 2016 में CM थे, और 2019 में अभी भी CM हैं) द्वारा चुनौती दी गई थी और 2005 में अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था, मुख्यतः सबूत के बोझ के स्थानांतरण के कारण व अन्य कारणों से भी। एक बार ऐसा होने के बाद, केंद्र सरकार ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर, 1964 में यह कहने के लिए संशोधन किया कि उक्त आदेश असम पर लागू नहीं होगा। विदेशियों का पता लगाने के लिए विभिन्न न्यायाधिकरणों का गठन करने वाले असम के लिए एक अलग आदेश जारी किया गया था। परन्तु सोनोवाल ने इसे भी चुनौती दी और इन आदेशों को 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। परिणामस्वरूप, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 असम पर लागू होता है और इस आदेश के तहत विदेशी ट्रिब्यूनल असम में गठित किए जाते हैं।

1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और नतीजतन 1987 में नागरिकता अधिनियम,1955 में संशोधन कर के केवल असम में लागू करने के लिए धारा 6A के प्रावधान को शामिल किया गया। इस खंड के निम्नलिखिति बिंदु हैं:

(a) कि असम राज्य के लिए वे सभी व्यक्ति जो 1.1.1966 से पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए थे और जो तब से असम के सामान्य निवासी हैं, उन्हें 1.1.1966 से भारत के नागरिक माना जाएगा।

(b) जो लोग 1.1.1966 से 25.3.1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान में असम में प्रवेश कर वहां निवास कर रहे हैं और उन्हें एक विदेशी के रूप में पाया गया है जो संबंधित प्राधिकरण के पास पंजीकृत होंगे। प्राधिकरण अगर यह महसूस करता है कि व्यक्ति मानदंडों को पूरा करता है तो वह ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत करेगा और यदि यह महसूस करता है कि ऐसा व्यक्ति मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो यह मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स को संदर्भित करेगा। ऐसे व्यक्ति को विदेशी के रूप में उसकी पहचान की तारीख से 10 साल के अंत में भारत का नागरिक माना जाएगा। इस अवधि तक, उसके पास अन्य अधिकार होंगे लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा। 10 साल के बाद उसके पास भारतीय नागरिक के सभी अधिकार होंगे।

(c) Section 6A (7) कहता है कि इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो 7.12.1985 से पहले भारत का नागरिक है। 1985 से पहले भारत भर में नागरिकता जन्म से थी और यदि 25.3.1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासी 7.12.1985 से पहले भारत में बच्चे को जन्म देते हैं, तो ऐसे बच्चे को भारत का नागरिक माना जाएगा। संक्षेप में, यह धारा प्रदान करती है कि जो लोग 25.3.1971 के बाद बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किये, वे भारतीय नागरिकता के हकदार नहीं होंगे।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर, 1964, के अनुसार पूरे भारत में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्थापित किया जा सकता है। और यह विदेशियों का पता लगाने के तरीके भी निर्धारित कर सकता है। यह ऑर्डर किसी कानूनके द्वारा या संसद द्वारा चर्चा कर के पारित नहीं किया गया है, बल्कि इसे कार्यकारी आदेश (सरकार) के माध्यम से पारित किया गया है।

किसी व्यक्ति के बारे में केंद्र सरकार या किसी सक्षम पदाधिकारी (जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित किया गया है) द्वारा ट्रिब्यूनल में एक संदर्भ दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, सुनवाई की अनुमति दी जाएगी और फिर एक आदेश पारित किया जाएगा। यह आदेश है जिसने असम बॉर्डर पुलिस को समन जारी करने का अधिकार दिया है। इस आदेश के तहत निहित शक्तियों के माध्यम से, असम सीमा पुलिस गवाहों को तलब कर सकती है, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य ले सकती है। 2013 में एनआरसी प्रक्रिया में तेजी आने से काफी पहले से असम बॉर्डर पुलिस विदेशी नोटिस ट्रिब्यूनलों के समक्ष पेश होने की कठिन प्रक्रिया के लिए ऐसे नोटिस जारी कर रही है।

17 जुलाई, 1997 को चुनाव आयोग ने असम सरकार को एक परिपत्र जारी किया जिसमें गैर-नागरिकों को मतदाता सूची से हटाने का निर्देश दिया गया। इसके बाद मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर डोर-टू-डोर सर्वे किया गया। जिन मतदाताओं को अपनी भारतीय राष्ट्रीयता साबित करने में असमर्थ माना जा रहा था, मतदाता सूची में उनके नाम के पहले D यानि डाउटफुल अक्षर लगा दिया गया। बहुत सारे मतदाता जो अनुपस्थित थे उन्हें भी D से चिन्हित किया गया था।

2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि असम एक ऐसा राज्य है, जहाँ की 54 प्रतिशत आबादी जन्म से ही आंतरिक रूप से पलायन करती है। यह बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित एक राज्य है जो न केवल विस्थापन का कारण बनता है, बल्कि नदी क्षेत्र के गांवों का फिर से विन्यास 'गायब हो जाता है' और नए पैदा होते हैं। बाढ़ की आपदा, आजीविका असुरक्षा, और आंतरिक पलायन के प्राथमिक कारण के रूप में क्षरण; विस्थापितों में से कई अपनी सामाजिक-आर्थिक पूंजी का उपयोग समुदाय और बंजर भूमि में फिर से खोजने के लिए करते हैं, जिसका उनके पास "पट्टा" नहीं है।

विधानसभा घटक मानचित्रण द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक अध्ययन में वोटरों ने खुलासा किया कि अधिकांश D-वोटर ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो इलाके बाढ़-कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। घोषित D-वोटर और नागरिकता से वंचित लोगों में 62 प्रतिशत महिलाएँ हैं।

यह अध्ययन सीजेपी ने प्रकाशित किया था- cjp.org.in (https://cjp.org.in/disasters-displacement-and-political-dis-enfranchisement-in-a-warming-world/)

26 मार्च, 2018 को असम के परिवहन मंत्री (पहले राज्य विधानमंडल सदस्य), चंद्रमोहन पटोवरी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2017 तक कुल 2,44,144 लोगों को डी वोटर चिह्नित किया गया था। इनमें से 1,31,034 मामलों का 31 दिसंबर, 2017 तक फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के समक्ष निस्तारण किया गया।

ऐसा नहीं है कि केवल NRC अपवर्जन प्रक्रिया एकमात्र प्रक्रिया है जो हाशिए पर के वर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, इसके आलावा डी-वोटर्स और किसी को "संदिग्ध/संदेहास्पद" (suspected/doubtful) बना कर "उन्हें भारतीय नागरिक साबित करने" का बोझ भी हाशिए पर के लोगों का जीना मुहाल कर रहा है।

यह जानना महत्वपूर्ण है कि, असम के अलावा, इन न्यायाधिकरणों को कहीं भी स्थापित नहीं किया गया है। आमतौर पर बिन पासपोर्ट या बिन दस्तावेजों के यात्रा करने वाले विदेशियों को (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत गिरफ्तार किया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है।

नागरिकता पंजीकरण नियम, 2003 (NRC नियम) 2009 में नियम 4A को शामिल करके असम के लिए संशोधित किया गया है, जिसमें पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए भारत के अन्य हिस्सों की तरह डोर टू डोर सर्वेक्षण नहीं बल्कि असम के सभी निवासियों से आवेदन आमंत्रित करना आवश्यक है। असम के लिए भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) की तैयारी की प्रक्रिया को रेखांकित करने वाले नियमों में एक अनुसूची जोड़ी गई है। यह मसौदा एनआरसी और बाद में अंतिम एनआरसी तैयार करने की विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। खण्ड 8 कहता है कि यदि आपका नाम अंतिम एनआरसी से गायब है, तो आप विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

असम के लिए, 1964 के आदेश को खंड 1B और 3A को शामिल करके संशोधित किया गया है। जबकि विदेशी ट्रिब्यूनल के अन्य प्रावधान असम में लागू होते हैं, क्योंकि NRC से संबंधित कुछ विशेष प्रावधानों के कारण, अब विदेशी ट्रिब्यूनल को NRC को अंतिम रूप देते समय पारित आदेशों से एक अपील प्रदान की जाती है। इस प्रकार, जब 31.8.2019 को एनआरसी के असम के लिए अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी, जो सूची में नहीं थे, वे विदेशी ट्रिब्यूनलों के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं और यदि विदेशी ट्रिब्यूनल में वे नागरिकता साबित नहीं कर पाए तो उन्हें अंततः विदेशियों के रूप में घोषित किया जाएगा।

भाग दो: असम

असम राज्य के लिए NRC अपडेशन प्रक्रिया का क्या अनुभव है, एकमात्र राज्य जिसने अभी तक इस तरह की प्रक्रिया को अंजाम दिया है?

नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स, असम को समझने के लिए एक अद्वितीय प्रक्रिया है, जो असम समझौते से पहले के वर्षों के बाद आई थी, जब आक्रामकता, संघर्ष और हिंसा ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया था जो बाहरी व्यक्ति के वास्तविक या काल्पनिक भय से प्रेरित थी।

स्वतंत्रता के बाद और विभाजन

1951 जनगणना: 1951 की जनगणना के अनुसार भारत में 306 मिलियन (84.1%) हिंदू और 34 मिलियन (9.8%) मुस्लिम थे। (आज़ादी के बाद की पहली जनगणना और भारत का विभाजन)। विस्थापितों की 1951 की जनगणना के आधार पर, 72.26 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान (पश्चिम और पूर्व दोनों) गए, जबकि 72.49 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान (पश्चिम और पूर्व दोनों) से भारत आए।

NRC 1951: नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर, 1951 सामाजिक-आर्थिक स्थिति का एक रजिस्टर है, जिसे प्रत्येक गाँव के संबंध में 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया है। जनगणना के बाद एक क्रम में घरों या होल्डिंग्स को दिखाना और प्रत्येक के बारे में संकेत करना उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या और नाम आदि की जानकरी इसमें दी गई। असम देश का एकमात्र राज्य है जिसने 1951 में 80 लाख नागरिकों के साथ उस वर्ष की जनगणना के आधार पर एनआरसी तैयार किया था। देश के किसी अन्य राज्य में 1951 में NRC नहीं था।

ये रजिस्टर 1951 में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार उपायुक्तों और उप-मंडल अधिकारियों के कार्यालयों में रखे गए थे। बाद में इन रजिस्टरों को 1960 के दशक की शुरुआत में पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया था।

NRC 1951 पूरा नहीं हुआ था

NRC 1951 दस्तावेज़ पूर्ण सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण नहीं था और जैसा कि यह एक गुप्त प्रशासनिक दस्तावेज़ था, लोग इसे सत्यापित नहीं कर सकते थे। असम सरकार ने राज्य विधानसभा में स्वीकार किया कि 1951 का एनआरसी छह जिलों के लिए उपलब्ध नहीं है: कछार, करबियांगलांग, बक्सा, चिरांग, दीमा हसाओ और शिवसागर। अकेले तिनसुकिया जिले में 1951 NRC में 626 गाँवों के नाम उपलब्ध नहीं हैं, जबकि नलबाड़ी, बारपेटा, लखीमपुर जिलों में, 200 से अधिक गाँवों के डेटा / नाम उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी आंकड़ों में यह भी उल्लेख है कि नलबाड़ी में, 1951 एनआरसी 481 गांवों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई है, जबकि लखीमपुर जिले के 523 गांवों का एनआरसी डेटा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया

है। इसे देखते हुए, एनआरसी 1951 असम में मौजूदा तौर-तरीकों के तहत आधार दस्तावेज कैसे बन सकता है? यह एक रहस्य बना हुआ है।

ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (आसू) की 1951 एनआरसी को राज्य में 'विदेशियों' की पहचान बनाने का आधार बनाने की मांग का विरोध करते हुए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के 21 फरवरी 1981 के अंक में अनिल रॉय चौधरी ने लिखा, वे जनगणनाकर्ता थे जिनके द्वारा जनगणना की गई थी। इसका आधार जनगणना के दौरान एकत्रित जानकारी थी। प्रगणकों को केवल 20 दिनों में गणना का कार्य पूरा करना था। यदि किसी क्षेत्र में कम-गणना के कारण या अन्यथा किसी व्यक्ति का नाम जनगणना में छोड़ दिया गया था, तो उसका नाम स्वतः ही NRC से भी बाहर कर दिया गया था, और यदि किसी व्यक्ति को आकस्मिक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था, तो उसके पास नाम दर्ज कराने का कोई अवसर नहीं था। बाद में एन.आर.सी. पर वह आपत्तियां भी दर्ज नहीं करा सके। चूंकि NRC को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया था और वह सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं था, इसलिए एक व्यक्ति को यह भी नहीं पता चल सकता था कि उसका नाम सभी में शामिल है या नहीं। रजिस्टर में दर्ज होने से छूटे व्यक्तियों के भयावह परिणामों के बारे में लोगों को कोई संकेत नहीं दिया गया था जो भविष्य की तारीख में उन्हें ओवरटेक कर सकते हैं यदि उनका नाम नागरिक रजिस्टर, 1951 में शामिल नहीं किया गया तो। उस समय किसी को भी पता नहीं था कि 'अयोग्य' या 'अप्रशिक्षित' प्रगणकों की गलती या अक्षमता के कारण वह और उसके वंशज भविष्य की तारीख में विदेशी के रूप में घोषित किए जाएंगे और निर्वासन का सामना करेंगे।"

इस इतिहास को याद रखना चाहिए क्योंकि भारत अब एक अखिल भारतीय स्तर पर NRC का सामना कर सकता है।

"घुसपैठिए" बयानबाजी बनाम तथ्य (डेटा): असम

'घुसपैठिये' और पीआईपी योजना (1961-1964): 1961 की जनगणना पर अपनी रिपोर्ट में, जनगणना के रजिस्ट्रार जनरल ने मूल्यांकन किया कि 2 लाख से अधिक घुसपैठियों ने असम में प्रवेश किया था। पुलिस ने बाद में इन 'घुसपैठियों' का पता लगाने और निर्वासित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। फिर 1998 में, असम के राज्यपाल एस के सिन्हा की एक रिपोर्ट में बांग्लादेश से अवैध आव्रजन द्वारा उत्पन्न 'गंभीर खतरे 'पर प्रकाश डाला गया, हालांकि शिक्षा जगत और मानवाधिकारों के कई लोगों ने इस बयानबाजी के पीछे डेटा की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। भारत के पूर्व गृह मंत्री, इंद्रजीत गुप्ता ने संसद में कहा कि असम में अवैध प्रवासियों की बताई जा रही भारी संख्या डेटा पर आधारित नहीं है। इसी तरह सार्वजनिक भाषण लोगों को प्रभावित करते रहे और भारत ने यह मानना शुरू कर दिया कि वहाँ 1.20 करोड़ 'घुसपैठिए'थे! इस बीच यहां तक कि भारत की सर्वोच्च अदालत, दो महत्वपूर्ण निर्णयों, सर्बानंद सोनोवाल, 2005 और 2007, मे "अवैध प्रवासन" के बारे में प्रचलित हिस्टीरिया में 'बाहरी आक्रामकता' से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का उल्लेख करता है। जून 1962 में, "पाकिस्तानी देशों की भारत में घुसपैठ की रोकथाम", या पीआईपी योजना की स्थापना सीमा क्षेत्रों में मौजूदा निवासियों की आवाजाही पर निगरानी रखने और टैब रखने के लिए एक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी। नए प्रवेशकों के लिए किसी का ध्यान नहीं जाना बेहद मुश्किल है। इस योजना के तहत, सरकार ने 'घुसपैठियों 'की निम्नलिखित तीन श्रेणियों को संक्षेप में प्रस्तुत करने का फैसला किया: पाकिस्तानी

नागरिक जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते थे, वे घुसपैठिये जो एक बार निर्वासित हो गए थे, और नए घुसपैठिए जिन्हें बॉर्डर पर पकड़ा गया।

1964 में, फॉरेनर्स (ट्रिब्यूनल) का आदेश पारित कर. असम में रहने वाले संदिग्ध 'विदेशियों' सुनवाई के लिए विदेशी प्राधिकरण बनाए गए। 'घुसपैठियों'और 'विदेशियों 'को भारत छोड़ो नोटिस दिया गया था, और एक लाख से अधिक लोगों को बिना निरीक्षण के जबरन निर्वासित कर दिया गया। 1965 से, चुनिंदा क्षेत्रों के भारतीय निवासियों को पहचान पत्र जारी किए जाने लगे ताकि वे पाकिस्तानी घुसपैठिये बनने की गलती से बचने के लिए स्वेच्छा से उन्हें कैरी कर सकें। यह असम पुलिस सीमा संगठन की उत्पत्ति थी जो 1974 में असम पुलिस की सीमा संगठन या सीमा शाखा के रूप में स्वतंत्र रूप से संचालित होने लगी।

1979 असम आंदोलन: मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र में उपचुनावों के दौरान, बड़ी संख्या में संदिग्ध विदेशियों के मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाने के व्यापक आरोप लगे। यह तब था जब असम आंदोलन का जन्म हुआ था। इसका नेतृत्व AASU (ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन) ने किया था। 1983 नेली नरसंहार: हाशिए पर पड़े असमिया मुसलमानों का भारत का पहला स्वातंत्र्योत्तर नरसंहार 18 फरवरी, 1983 को हुआ था: "अवैध प्रवासियों" के मुद्दे को लेकर बनाए गए लक्षित उन्माद में 2,500 मासूमों ने अपनी जान गंवाई थी। आज, नरसंहार के 36 साल बाद, जिसमें देखा गया कि जीवित बचे लोगों के साथ ऐसा कोई न्याय नहीं किया जा रहा है, किसी भी अपराधी को सजा नहीं दी जा रही। बोरबरी (नेली) गाँव के विभिन्न जाति व समुदायों के 40 प्रतिशत पीड़ित निवासियों ने एनआरसी और फॉरेन ट्रिब्यूनल्स का सामना किया है।
(Https://cjp.org.in/36-years-on-survivors-of-nellie-massacre-suffer-in-perpetuity-40-out-of-nrc/)

असम समझौता (1985): असम समझौते पर 1985 में 6 साल के लंबे आंदोलन के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। राजीव गांधी ने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। ऐतिहासिक समझौते पर 15 अगस्त 1985 को हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते का खंड 5 प्रदान करता है:

1. विदेशियों का पता लगाने और हटाने के प्रयोजनों के लिए, 1 जनवरी, 1966 आधार तिथि होगी। उस तारीख से पहले असम आने वालों को नियमित किया जाएगा।

2. जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 24 मार्च 1971 के बाद असम आए, उन्हें Foreigners (Tribunals) Order 1964 के तहत संदर्भित किया जाएगा।

असम में NRC के तौर-तरीके (अब तक)

एनआरसी प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले तौर-तरीके एक आम सहमति के आधार पर तैयार किए गए थे, जो इस मामले के सभी हितधारकों, जैसे कि असम आंदोलन, विभिन्न धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों और असम के सभी राजनीतिक दलों की मांग के अनुसार।

विरासत और संबंध: विस्तृत चर्चा के बाद, यह निर्णय लिया गया कि भारतीय नागरिकता की वास्तविकता दो प्रकार के प्रलेखन: विरासत और लिंकेज द्वारा निर्धारित की जाएगी। "विरासत दस्तावेज" 25 मार्च 1971 से पहले किसी व्यक्ति या उनके पूर्वज की नागरिकता स्थापित करते हैं। उन्हें सूची A दस्तावेजों के रूप में संदर्भित किया गया था। NRC असम की वेबसाइट के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी (24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि से पहले जारी) स्वीकार किया जाएगा:

1) 1951 एनआरसी

2) 24 मार्च 1971 (मध्यरात्रि) तक मतदाता सूची

3) भूमि और किरायेदारी रिकॉर्ड्स

4) नागरिकता प्रमाण पत्र

5) स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र

6) शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र

7) पासपोर्ट

8) एलआईसी

९) सरकार द्वारा जारी कोई लाइसेंस / प्रमाण पत्र

10) सरकारी सेवा / रोजगार प्रमाण पत्र

11) बैंक / डाकघर खाते

12) जन्म प्रमाण पत्र

13) बोर्ड / विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रमाण पत्र

14) कोर्ट रिकॉर्ड्स / प्रक्रियाएं।

इसके अलावा, दो अन्य दस्तावेज अर्थात (1) सर्किल ऑफिसर/ ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सर्टिफिकेट शादी के बाद पलायन करने वाली महिलाओं के संबंध में (24 मार्च से पहले या उसके बाद किसी भी वर्ष का हो सकता है), और (2) 24 मार्च, 1971 की आधी रात तक जारी किया गया राशन कार्ड सहायक दस्तावेजों के रूप में जोड़ा जा सकता है। हालांकि, इन दोनों दस्तावेजों को केवल तभी स्वीकार किया जाएगा, जब उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी एक के साथ लिस्टेड होंगे।

दूसरी आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब सूची A के किसी भी दस्तावेज में आवेदक का स्वयं का नाम नहीं होता है, बल्कि उसके पूर्वज, पिता या माता या दादा या दादी या परदादा या परदादी या परदादी इत्यादि का होता है। ऐसे मामलों में, आवेदक को ऐसे पूर्वज, अर्थात, पिता या माता या दादा या दादी या परदादा या परदादी आदि के साथ संबंध साबित करने के लिए नीचे सूची बी में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनका नाम सूची ए के दस्तावेजों में दिखाई देगा।

इसके लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज होना चाहिए जो इस तरह के संबंधों को स्पष्ट रूप से साबित करता है।

(1) जन्म प्रमाण पत्र या

(2) भूमि दस्तावेज या

(3) बोर्ड / विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र या

(4) बैंक / एलआईसी / डाकघर रिकॉर्ड या

(5) विवाहित महिलाओं के मामले में सर्किल अधिकारी / ग्राम पंचायत सचिव प्रमाणपत्र या

(6) इलेक्टोरल रोल या

(7) राशन कार्ड या

(8) कोई अन्य कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज

24 मार्च, 1971 की मध्यरात्रि तक किसी भी अवधि की लिस्ट A के दस्तावेजों में से किसी एक को प्रदान करना एनआरसी में शामिल करने के लिए पात्रता साबित करने के लिए पर्याप्त होगा।

"लिंक दस्तावेज़" 1971 से पूर्व भारतीय पूर्वजों, या उनके "विरासत व्यक्तियों" के बाद पैदा हुए लोगों के साथ हल्का लिंक स्थापित करते हैं। उन्हें लिस्ट बी दस्तावेज़ भी कहा जाता है। NRC असम की वेबसाइट में कहा गया है कि लिस्ट A के किसी भी दस्तावेज में आवेदक के स्वयं के बजाय पूर्वज का नाम है, तो लिस्ट बी का दस्तावेज दिखाने की आवश्यकता होगी।

कमजोर दस्तावेज: जबकि एनआरसी प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, कुछ दस्तावेज बेवजह और मनमाने ढंग से मांगे गए-- जिनको नागरिकता के वैध प्रमाण के रूप में बहुत कमजोर घोषित किया गया। ऐसा ही एक दस्तावेज 1971 से पहले का राशन कार्ड था, जो अक्सर गरीब, श्रमिक वर्ग के परिवारों का एकमात्र दस्तावेजी प्रमाण होता है। इसी तरह, सर्किल अधिकारियों / ग्राम पंचायत सचिवों और पंचायत लिंक प्रमाणपत्रों द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्रों को समाप्त करने से विवाहित महिलाओं पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए कुछ दस्तावेजों को समान रूप से ध्यान में नहीं रखा गया था।

वैकल्पिक प्रावधान: दो प्रावधान- **डीएमआईटी** और **डीएनए** परीक्षण से उन लोगों की नागरिकता स्थापित करने में मदद मिल सकती थी जो अपनी प्रलेखन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे थे, लेकिन अंततः ये उपयोगी प्रावधान प्रक्रिया से हटा दिए गए।

यदि कोई वास्तविक भारतीय नागरिक उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहा, तो उनके मामले की जाँच जिला मजिस्ट्रेट जाँच दल या DMIT द्वारा स्वतंत्र रूप से की जा सकती है, जो किसी अनाथ, बेसहारा या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम को शामिल करने की मंजूरी दे सकता है, जिसके पास स्थानीय लोगों से जानकारी इकट्ठा करने के अलावा कोई दस्तावेज नहीं है।

डीएनए टेस्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता विरासत के आधार पर साबित करने के लिए सबसे उत्तम था लेकिन आरजीआई कार्यालय द्वारा यह प्रावधान एकतरफा रूप से हटा दिया गया।

बहिष्करण: सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश (13 अगस्त, 2019 को पारित) के परिणामस्वरूप उन व्यक्तियों का बहिष्कार हुआ, जो या जिनकी विरासत का व्यक्ति डी-वोटर था, एक घोषित विदेशी, या जिसका मामला फॉरेन ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है।

असम में अद्वितीय रूप से चलने वाली अन्य समवर्ती विदेशी खोज प्रक्रियाओं को एनआरसी प्रक्रिया के साथ मिश्रित और सीमित कर दिया गया था, हालांकि शुरुआत में यह प्रक्रिया नहीं थी। पहले देखे जाने वाले तौर-तरीके, जिन्हें "स्वतंत्र और निष्पक्ष" माना जाता था क्योंकि वे असम में विभिन्न हितधारकों के बीच सहमति से स्थापित किए गए थे, उनमें हेरफेर किया गया था और यहां तक कि पर्दा डाला गया था: यह सर्वसम्मति को कम करने का एक स्पष्ट प्रयास था।
(https://cjp.org.in/how-a-government-and-bureaucracy-betrayed-its-people/)

असम की एनआरसी अंतिम प्रक्रिया के दौरान, बड़ी संख्या में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि नाम, पदवी में मामूली विसंगतियां, विरासत के दस्तावेजों में उम्र में अंतर था। इस तथ्य के बावजूद कि NRC के राज्य के तौर-तरीके 'अन्यथा: नाम, आयु, शीर्षक की मामूली विसंगतियां अद्यतन NRC में नाम शामिल करने की वैध मांग को प्रभावित नहीं करेंगी। जमीनी स्तर पर 1,200 से अधिक नागरीक सेवा केंद्रों पर यह विशिष्ट आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे अन्याय और सामूहिक बहिष्कार हो रहा है।

असम में आबादी का ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे इस अति-शक्तिशाली त्रासदी ने अप्रभावित छोड़ दिया गया हो। बंगाली भाषी हिंदू, मुस्लिम, गोरखा, उत्तर और पश्चिम भारत के हिंदी भाषी लोग, सभी समान रूप से इसकी पकड़ में हैं। यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए घर से दूर जगहों पर होने वाली सुनवाई में भाग लेने के लिए आवेदन में बहुत धन खर्च करना है। इससे भी बदतर, उन्हें एक बार नहीं, बल्कि बार-बार, 'विरासत वाले व्यक्तियों' के साथ बुलाया जाता है। इसका मतलब है कि, कुछ मामलों में, कई लोगों को अपने पूरे परिवार के सदस्यों की मंडली के साथ 7 से 14

बार सुनवाई में भाग लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि एक विस्तारित परिवार के 40-80 लोगों का एक बैच अपने निवास स्थान से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करता है। हाल ही में दिल्ली के एक प्रमुख विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को दिल्ली से लखीमपुर के लिए ऊपरी असम में तीन बार भागना पड़ा था - जो कि उनके सभी परिवार के सदस्यों के साथ लगभग 3,000 किलोमीटर की दूरी पर है।

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल: असम और पूरा भारत

फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (एफटी) का गठन विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 1964 के तहत किया जाता है, जो कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, 1946 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपनी शक्तियों के प्रभाव में पारित किया जाता है। आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को संदर्भित करना है। यह सवाल कि क्या कोई व्यक्ति Foreigners Act, 1946 के अर्थ के भीतर एक विदेशी है, इस उद्देश्य के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी क़ानून के तहत स्थापित इन विदेशी ट्रिब्यूनलों को फिर से वैध कर दिया है

भारत के संविधान के Article 258(2) में संसद को एक कानून बनाने की आवश्यकता है जो सभी राज्यों पर लागू होता हो ताकि राज्य सरकार को उन मामलों में अधिकार मिल सके जिनके लिए राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। मामले में, भारत के संविधान के Article 258(2) द्वारा संदर्भित कानून Foreigners Act, 1946 है, जो पूर्व-संवैधानिक कानून है और भारत के संविधान के Article 13 का परीक्षण पारित कर चुका है। हालाँकि, Foreigners Act, 1946 में कोई प्रावधान राज्य सरकार को नहीं है। इस प्रकार, राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं था कि वह इस अधिनियम के अर्थ के भीतर एक व्यक्ति है, या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए Foreigners Tribunals का गठन करना है। समय-समय पर, 1948 के बाद 1964 में, विदेश मंत्रालय ने Foreigners Tribunals को असम में एक ऑर्डर के माध्यम से स्थापित किया था।

अब जब अखिल भारतीय स्तर पर NRC की चर्चा है, तो MHA (गृह मंत्रालय) ने 30.08.2019 के आदेश के माध्यम से, Foreigners Act, 1946 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, (Foreigners (Tribunals) में (दूसरा) (2019) संशोधन किया है। इस संशोधन के माध्यम से, पैरा 3 ए के तहत अपील करता है कि अनुसूची के अनुच्छेद 8 में "नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003" को जोड़ा गया है; इस प्रकार अब एफटी को अखिल भारतीय आधार पर लागू किया जा रहा है।

डिटेंशन कैंप

असम में डिटेंशन कैंपों में डरावनी कहानियों की भरमार रही है। अब, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने भी डिटेंशन कैंप स्थापित करने की घोषणा की है। जुलाई 2019 में, केंद्र सरकार ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को "मॉडल डिटेंशन सेंटर / होल्डिंग सेंटर / मैनुअल" प्रसारित किया है। हालाँकि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतियां अभी भी उपलब्ध नहीं हैं। हमारे पास यह जज करने का कोई तरीका नहीं है कि वे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। केंद्र सरकार ने स्थानीय राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर विदेशियों का पता लगाने के लिए

"सलाह" भी जारी की है।

Foreigners Tribunals का कार्य : FTs का कामकाज तेजी से आलोचना के दायरे में आया है। उनके कामकाज में उचित प्रक्रिया की अनुपस्थिति, उनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया और पारदर्शिता की अंतर्निहित कमी ने आलोचना को जन्म दिया है। ट्रिब्यूनल के प्रमुखों को न्यायिक जानकारी नहीं होने से सवाल खड़े हो रहे हैं।

NRC की कीमत

एक मानवाधिकार संगठन द्वारा चार जिलों में किए गए सर्वेक्षण में पाया गया है कि असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) के मसौदे से बाहर रहने वालों ने NRC की सुनवाई के लिए 7,836 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इनमें से कई इतने आर्थिक रूप से तंग हैं कि वे Foreigners Tribunals के सामने खुद के बहिष्कार को चुनौती देने में सक्षम नहीं हैं। बक्सा, गोलपारा और कामरूप जिलों में किए गए इस सर्वेक्षण में पाया कि 62 उत्तरदाता एनआरसी अधिकारियों के समक्ष सुनवाई में भाग लेने के लिए किए गए व्यय को निर्धारित करने में सक्षम थे और उन्होंने कुल 11,82,000 रुपये खर्च करने का दावा किया जो 19,065 रुपये प्रति व्यक्ति है।

विश्व बैंक ने 20 जून, 2017 को अपनी रिपोर्ट "असम: गरीबी, विकास और असमानता" में कहा था कि असम न केवल आर्थिक विकास में अधिकांश भारतीय राज्यों से पीछे है, बल्कि "गरीबी में कमी आने की दर 2005 के बाद असम में सबसे धीमी रही है। असम में गरीबी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, राज्य के कुछ हिस्सों में गरीबी का स्तर बहुत अधिक है। क्या यह संयोग है कि ये वो साल थे जब राज्य की 12 प्रतिशत आबादी इस नागरिकता के संकट से जूझ रही थी?

उदाहरण: उदाहरण के लिए, लोअर असम में गोलपारा जिले के कृष्णाई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले अशुदुबी गांव के सुब्रत डे का मामला लें। मई, 2018 में गोलपारा के डिटेंशन कैंप में डे की मृत्यु हो गई। उनकी मां अनिमा के अनुसार, "हमें एफटी में अपने बेटे के केस से लड़ने के लिए वकील की फीस और अतिरिक्त खर्च के रूप में लगभग एक लाख रुपये खर्च करने पड़े। सुब्रत को विदेशी घोषित किए जाने के बाद एक डिटेंशन कैंप में भेज दिया गया, हमने अपने घरेलू मवेशी और कुछ अन्य संपत्ति बेच दी और दो लाख रुपये इकट्ठा किए, जिसे हमने एक वकील को उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए दे दिया। लेकिन सुब्रत की मृत्यु तक, दो साल में भी मामला सुनवाई तक नहीं पहुंचा!"

इसी तरह, उदलगुरी जिले के रावत बागान क्षेत्र में, जोबर अली को जब विदेशी घोषित कर तेजपुर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया तो उन्होंने एफटी में अपने मामले को लड़ने के लिए एक वकील को 50,000 रुपये दिए। उनके परिवार के सदस्यों ने ऋण लेकर 1,00,000 रुपये गुवाहाटी न्यायालय के एक प्रख्यात वकील को इस उम्मीद में दिए थे कि जोबर अली घर आ जाएंगे। लेकिन जोबर अली ने दो साल डिटेंशन सेंटर में गुजारने के बाद वहीं दम तोड़ दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयंभू मानवतावादी अल्पसंख्यक अधिकारों के पैरोकार जिन्होंने अपना मामला उठाया था, ने मामले को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आगे बढ़ाने का कारण नहीं बनाया। इसी तरह, बारपेटा रोड के अमृत दास ने अपना केस लड़ने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधिवक्ता को 60,000 रुपये दिये इससे पहले वे इसी मामले में

60,000 रुपये और खर्च कर चुके थे। इस सबके बावजूद डिटेंशन सेंटर में ही उनकी जान चली गई।

एक अन्य उदाहरण में, चिरांग जिले के फरमाइशाली गाँव के निवासी सहर अली ने एक वकील को 50,000 / - रुपये का भुगतान किया और तीन साल के लिए एफटी में नियमित सुनवाई में भाग लेने के लिए 30,000 रु अतिरिक्त खर्च किए थे। उन्हें ऐसा व्यक्ति घोषित किया गया था जिसे 1966 से 1971 के बीच भारतीय क्षेत्र में आया माना जाता है। हालांकि उनका नाम 1951 NRC और 1971 की मतदाता सूची में था। एक भारतीय के रूप में वह काफी खुशकिस्मत हैं कि उनका नाम Foreigner's Regional Registration Office (FRRO) में उनके अधिवक्ता द्वारा उनकी जानकारी के बिना दर्ज किया गया है।

लेकिन उसी जिले के अंतर्गत आने वाले गाँव ऑक्सिगुड़ी के रवीन्द्र मलिक को 1999 में स्ट्रीमलाइन विदेशी घोषित किया गया था, लेकिन उनका नाम FRRO में पंजीकृत नहीं था। इस कारण से, रवीन्द्र मलिक को हिरासत में लिया गया और गोलपारा डिटेंशन कैंप में ले जाया गया, जहाँ वे 21 सितंबर, 2016 से बंद हैं। रवीन्द्र मलिक के परिवार के सदस्यों के अनुसार, उन्होंने एफटी में एक वकील को 60,000 / - रुपये का भुगतान किया और हाई कोर्ट में लड़ने के लिए दूसरे वकील को 1,50,000 रुपये दिए।

एनआरसी प्रक्रिया ने असम में करोड़ों भारतीय नागरिकों को प्रभावित किया है।

इन महंगी सुनवाइयों और भागदौड़ को देखते हुए सवाल उठता है कि, क्या भारत NRC का खर्च उठा सकता है?

भाग तीन: देशव्यापी: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) क्या है, जिसकी गणना अप्रैल 2020 से शुरू होगी और सितंबर 2020 में पूरी होगी? 2003 में, नागरिकता (नागरिक पहचान का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 नागरिकता अधिनियम के तहत पारित किए गए थे। ये NRC रूल्स हैं। इसके तहत, नागरिकता की स्थिति निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में एक घर से दूसरे घर तक ले जा सकती है। पहले चरण में यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के संकलन का परिणाम होगा। इस प्रक्रिया के दौरान, जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, उन्हें आगे की पूछताछ के लिए जनसंख्या रजिस्टर में चिह्नित किया जाएगा। सत्यापन के एक निर्धारित प्रारूप में इस बारे में समाप्त होने के तुरंत बाद व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा और, नियमों के अनुसार, किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सुनवाई के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

हालाँकि, नागरिकता के प्रमाण के लिए मानदंड / दस्तावेज क्या होगा अर्थात् एनपीआर में शामिल किए जाने या बहिष्करण के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।

31 जुलाई, 2019 को, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने नागरिकता (नागरिक पंजीकरण का पंजीकरण और

राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के अनुसरण में एक आदेश (SO 2753) जारी किया। जिसके तहत "सरकार जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने और उसे अद्यतन करने का फैसला करती है।" अधिसूचना के अनुसार, "असम को छोड़कर पूरे देश में घर घर गणना का काम" अप्रैल 2020 में शुरू होगा और सितंबर 2020 तक पूरा

हो जाएगा। आमतौर पर स्थानीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले लोग इस काम को पूरा करेंगे। 30 सितंबर 2009 को, एक अन्य अधिसूचना (G.S.R. 623 (E) के माध्यम से, Foreigners Tribunals 1964 के आदेशों में संशोधन किया और पूरे भारत में इनका विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और एनआरसी

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, भारत के अंदर और बाहर रहने वाले, और एक गाँव या ग्रामीण क्षेत्र या कस्बे या वार्ड या सीमांकित क्षेत्र (नागरिक पंजीकरण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सीमांकित) में रहने वाले नागरिकों के रजिस्टर का एकत्रीकरण है। जबकि एनपीआर नागरिकता का एक रजिस्टर है जो एक जनगणना के समान जो जनसंख्या के आंकड़ों, रुझानों और इतने पर निर्धारित करने के लिए जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित किया जाता है। इसलिए इसमें शामिल किए जाने और बहिष्कार के लिए मानदंड, नागरिकता अधिनियम के तहत निर्धारित कानून का पालन करना है, और सबूत (जन्म आदि) कानूनी तौर पर पेश करने के लिए हैं। भारत की जनगणना अपने अगले दौर के (2021) सर्वेक्षण करने के लिए निर्धारित है। इसलिए, यह मान लेना उचित है कि 2020 में एनपीआर का आयोजन एनआरसी के अंतिम अपडेशन के प्रयोजनों के लिए होने की संभावना है।

एक बार घर-घर गणना (अप्रैल - सितंबर 2020 के बीच) शुरू हो गई तो सभी नागरिकों को प्रक्रिया में संलग्न होना आवश्यक है। 2003 के नियमों के तहत, उप-जिला या तालुक रजिस्ट्रार टिप्पणी के 90 दिनों के भीतर अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा। किसी भी आपत्ति को आमंत्रित करने या किसी भी नाम को शामिल करने के लिए स्थानीय रजिस्टर का मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। 30 दिनों के भीतर व्यक्तियों को इस तरह की शिकायत के लिए प्रकृति और कारणों की वर्तनी पर आपत्ति या शिकायत करनी होती है। इन शिकायतों पर उप-जिला या तालुक रजिस्ट्रार द्वारा विचार किया जाएगा और 90 दिनों में संक्षेप में निपटाया जाएगा। उपरोक्त आदेशों से व्यथित व्यक्ति 30 दिनों तक नागरिक पंजीकरण के जिला पंजीयक के पास अपील कर सकता है।

जिला रजिस्ट्रार 90 दिनों के भीतर पार्टी की सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लेंगे। इसके बाद अंतिम रजिस्टर प्रकाशित किया जाता है और प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके तहत, Foreigners Tribunal की कम से कम कोई भूमिका नहीं है क्योंकि कानून आज भी खड़ा है। यदि आप एक नागरिक के रूप में पंजीकृत नहीं हैं, तो आपको विदेशी माना जाएगा और सभी परिणाम, डिटेंशन कैंप में भेजा जाना, निर्वासित होना, आदि भुगतने होंगे।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर उन सभी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करके तैयार किया जाएगा जो आमतौर पर स्थानीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

भाग चार: अखिल भारतीय: अखिल भारतीय NRC और इसका कानूनी आधार

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर क्या है और इसका कानूनी आधार क्या है? भारतीयों के लिए राष्ट्रव्यापी NRC का क्या अर्थ है?

क्या 2020 का एनपीआर अखिल भारतीय स्तर पर एनआरसी की ओर जाता है?

31.07.2019 की एमएचए गजट अधिसूचना राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने के लिए थी

• क्या इस एनपीआर का NRC से कोई संबंध है?

हां, नागरिकता नियमावली 2003 में निर्धारित तैयारी पद्धति के अनुसार, यह एनपीआर से है कि भारतीय नागरिक के स्थानीय रजिस्टर में अद्यतन के लिए डेटा (यानी एनआरसी का हिस्सा) जांच और सत्यापन के बाद लिया जाएगा।

• क्या 31 जुलाई, 2019 का एमएचए गजट, अखिल भारतीय एनआरसी के कार्यान्वयन की शुरुआत की अधिसूचना है?

NRC की तैयारी नागरिकता के नियम 4 (नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 में निर्दिष्ट की गई है। NRC की शुरूआत उपरोक्त नागरिकता नियमों के नियम 6 में निर्दिष्ट है। अब तक, नियम 6 के तहत विनिर्देशों को जारी नहीं किया गया है।

हालाँकि, चूंकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की तैयारी एक अखिल भारतीय NRC के लिए आवश्यक आधार है, और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली अधिकारियों द्वारा व्यापक बयान दिए गए हैं, यह समझना, समझदारी होगी कि वर्तमान में बिछाया जा रहा जाल अखिल भारतीय स्तर पर NRC लागू करने की तैयारी का आधार है।

हालाँकि, देशभर के लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित और जागरूक होना चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इसे इसके सभी आयामों में समझें और प्रश्न उठाएं। कई स्थानीय समुदाय पहले से ही दस्तावेजों को एक्सेस करने और जन्म प्रमाण पत्र सहित मौजूदा दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि उनका रिकॉर्ड सही ढंग से जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज हो जाए जो एनआरसी के लिए नींव होगी। कई स्थानीय समुदाय भी, गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि नामों में विसंगतियों को ठीक किया जाए।

NRC के विषय में असम और भारत के अन्य भागों के बीच अंतर

1. NRC नागरिकों का एक रजिस्टर है। इसलिए, NRC को लेकर असम और शेष भारत के बीच पहला अंतर यह होगा कि नागरिकता का हकदार कौन होगा। यह पहले से ही ऊपर बताया गया है।

2. दूसरा अंतर यह है कि जबकि, असम में व्यक्तियों को पंजीकृत होने के लिए आवेदन करना है, शेष भारत में व्यक्तियों को आवेदन नहीं करना है, लेकिन सरकार को घर-घर सर्वेक्षण करना है और जनसंख्या रजिस्टर में इसे शामिल करना है जो NRC मसौदा की तरह है। इसके बाद अंतिम रूप से NRC जारी किया जाएगा।

31.7.2019 को केंद्र सरकार ने 1.4.2020 से 30.9.2020 के बीच जनसंख्या रजिस्टर और हाउस टू हाउस सर्वे की तैयारी के लिए NRC नियमों के तहत एक अधिसूचना जारी की। यह इन तिथियों के आसपास है कि पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नागरिकों को सतर्क रहना होगा।

भाग पांच: कार्य योजना, हमें क्या करना चाहिए?

• NRC से निपटने की तैयारी करें जब तक कि भारत की जनगणना प्रक्रिया की तरह, यह समावेशी नहीं है

• निर्वाचित प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के संपर्क में रहें औऱ सरकार से प्रश्नों का जवाब मांगें।

सरकार से मांगें जवाब

• कट-ऑफ डेट: क्या यह 27 जनवरी, 1950 होगी?

• अपडेट दस्तावेज: हम और सभी नागरिक, जहां भी हम कर सकते हैं, लिस्ट के अनुसार हमारे वर्तमान दस्तावेजों को अपडेट करने और हमारे चुनावी रिकॉर्ड को

सुधारने में कोई बुराई नहीं है और यह सुनिश्चित करें कि हमारा सही डेटा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज किया गया है जो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा।

देशव्यापी NRC से संबंधित कुछ मुद्दे और प्रश्न

ऐसे समय में जब NRC को लेकर चिंता और दहशत देशव्यापी हो रही है, ऐसे में कुछ बुनियादी सवालों की अनदेखी की गई है।

एनआरसी के लिए कट-ऑफ डेट क्या होगी?

• हालांकि यह भारत में NRC के संबंध में अब तक कहीं भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अगर यह नागरिकों का पंजीकरण है, इसकी कटऑफ डेट 27 जनवरी,

1950 हो सकती है। यह मानते हुए कि 27 जनवरी, 1950 (भारतीय संविधान लागू होने का दिन) आधार तिथि है, इसलिए इस दिन नागरिकता पर कानून लागू होगा।

• 1950-1987: जन्म

1987-2004: माता या पिता में से एक भारतीय पैदा हुए हों।

2004 के बाद: एक अभिभावक भारतीय, दूसरा "अवैध प्रवासी" नहीं हो।

• 1951 एनआरसी के सत्यापन के लिए आधार दस्तावेज होने की कोई भी जानकारी गलत है क्योंकि 1951 एनआरसी केवल असम के लिए तैयार किया गया था इसमें अन्य राज्य के लिए कोई डेटा एकत्र नहीं किया गया था, इसलिए 1951 एनआरसी की प्रयोज्यता कहीं नहीं है।

एनपीआर में कट-ऑफ डेट, मोडैलिटी, इंक्लूजन फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्या होगा?

हमें ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है:

• सरकार का अखिल भारतीय NRC लागू करने के पीछे क्या सिद्धांत और दृष्टिकोण है?

• क्या भारतीय संवैधानिक दृष्टि से बाध्य सरकार, समावेश या बहिष्करण के एक निर्धारित दृष्टिकोण का पालन करेगी?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 में बहस को आमंत्रित करना चाहिए।

• मतदाता पंजीकरण: भारत में 100% मतदाता पंजीकरण नहीं है। यह चिंता का विषय है कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर खड़े वर्गों के लोगों को वोट देने के अपने मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

जब हम एक देश के रूप में सभी भारतीयों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो क्या हमसे निष्पक्ष पंजीकरण प्रक्रिया (एनपीआर या एनआरसी) होने की उम्मीद की जा सकती है?

• जन्म पंजीकरण आँकड़े: यूनिसेफ के अनुसार: देश में जन्म और मृत्यु का वर्तमान पंजीकरण स्तर लगभग 58% है। जब जन्म पंजीकरण भी शत-प्रतिशत नहीं हैं, तो हम पूरी तरह से एनपीआर / एनआरसी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?

• आवास सांख्यिकी: 2001 की जनगणना के अनुसार, लगभग 192 मिलियन घरों में 187 मिलियन घरों को निवास या सह निवास या अन्य उपयोग के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 24.67 करोड़ घर हैं।
(https://www.livemint.com/Opinion/a5jnMOHQsHEk47Rr9mUWPI/Five-charts-on-the-state-of-Indias-housing-sector.html)

एनपीआर/एनआरसी के लिए जमीन या घरों के मालिक नहीं होने से जरूरी सबूत/दस्तावेज के क्या मानक होंगे?

• प्रवासी श्रमिक: फिर उन लाखों भारतीयों का सवाल है जो प्रवासी श्रमिक हैं जो अपने निवास स्थान में नहीं रहते हैं।

एनपीआर / एनआरसी भारत के प्रवासी श्रम का पंजीकरण या रिकॉर्ड कैसे करेगा, जिनके पास कोई घर नहीं है और कोई जमीन नहीं है और उन्हें वोट का अधिकार भी नहीं दिया गया है। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं तक भी उनकी पहुंच नहीं है, उनके लिए (समावेशन / बहिष्करण) प्रकिया दुखदाई हो सकती है।

• यूनेस्को के अनुसार भारतीय साक्षरता दर (2018) 70.47% है। यदि प्रक्रिया, मानदंड, मोडेलिटी एनपीआर (जो कि हाउस टू हाउस सर्वे है) को सूचित करते हैं, तो उस जनगणना की तरह नहीं है जो जानकारी एकत्र कर रही है (समावेशी) यह असम की एक और आपदा में और भी खराब अनुपात में समाप्त होने की संभावना है।

इन आंकड़ों को देखते हुए, आखिरकार, समय की मांग है कि एक अखिल भारतीय NRC में भारी उथल-पुथल और आघात की संभावना है।

यदि 27 जनवरी, 1950 नागरिकता 'साबित करने' की आधार तिथि है, तो दस्तावेजी प्रमाण के लिए ऊपर दिए आंकड़ों के हिसाब से अधिकारियों का दृष्टिकोण क्या होगा।

क्या तौर-तरीके और मानदंड होंगे जो इस बात की रूपरेखा तैयार करते हैं कि एनपीआर में दर्ज नामों को बहिष्कृत करने के लिए कौन से प्रमाण / प्रमाण के मानक का उपयोग किया जाएगा जो आगामी एनआरसी का आधार है? कौन तय करेगा?

पक्षपातपूर्ण नागरिकता

यह सरकार भारतीय नागरिकता के आधार को संप्रदाय के आधार पर बहुत हद तक बदलने की योजना बना रही है। यह धार्मिक अल्पसंख्यकों (उन सभी को छोड़कर जो मुस्लिम हैं) को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (1955) में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, अगर वे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के तीन देशों से आते हैं और यदि वे दिखा सकते हैं। वे "सताए हुए अल्पसंख्यक" हैं।

2015 और 2016 में लाए गए नियमों में संशोधन

7 सितंबर, 2015 और 18 जुलाई, 2016 को Foreigners Order, 1948 में दो संशोधन लाए गए थे। पैराग्राफ 3 के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ सम्मिलित किया गया है: -

"3 ए. विदेशियों की कुछ निश्चित वर्ग में छूट- (i) बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्ति, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक भय के कारण भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए थे। जिन्होंने उत्पीड़न से आजिज आकर 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया-

पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियम, 1950, नियम 4 में, उप-नियम (i) में, खंड (h) के बाद, निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ha) बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित व्यक्तियों, अर्थात्, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर थे या 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किए थे। (i) पासपोर्ट या अन्य यात्रा के वैध दस्तावेजों के बिना; या (ii) पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज सहित वैध दस्तावेजों के साथ और ऐसे किसी भी दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है: बशर्ते कि इस खंड का प्रावधान आधिकारिक गैज़ेट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।"

2016 में, उपरोक्त नियमों में संशोधन किया गया था, यहां तक कि अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया था। संक्षेप में, इन नामित अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता नहीं मिलेगी लेकिन उन्हें हिरासत में या निष्कासित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा यदि वे दिखा सकते हैं कि वे उपरोक्त खंड के भीतर आते हैं।

अब, केंद्रीय विधानमंडल नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित करना चाह रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात्, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 (2) (c) के तहत छूट दी गई है या Foreigners Act, 1946 के प्रावधानों या उसके तहत किए गए किसी भी देश के आवेदन से अवैध नहीं माना जाएगा।

पासपोर्ट की धारा 3 (2) (c) (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, केंद्र सरकार को किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को देश में प्रवेश के लिए पूर्ण या सशर्त छूट प्रदान करने का अधिकार देता है, जिनके पास पासपोर्ट के कब्जे की आवश्यकता होती है।

असम में भारतीय नागरिकों का बचाव करने के लिए CJP का अभियान:

जब 31 दिसंबर, 2017 को असम में प्रकाशित हुए नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स (NRC) के आंशिक मसौदे से 1 करोड़ से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया, तो CJP कार्रवाई में आ गया। CJP ने जून 2018 में जमीनी हकीकतों का पता लगाने के लिए अपनी खुद की फैक्ट फाइंडिंग टीम असम भेजी। वहां से इस विषय के जानकारों द्वारा तैयार रिपोर्टों की छानबीन की गई। करीब एक हजार स्थानीय स्वयंसेवकों को असहाय और निर्धन लोगों की सहायता के लिए जुटाया।

30 जुलाई, 2018 को जारी किए गए पूर्ण मसौदे से अपवर्जन के संबंध में दावे दाखिल कराए। CJP यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध रहा कि किसी भी वास्तविक भारतीय नागरिक को नुकसान न हो।

अगस्त 2019 में सीजेपी अपने साथ प्रतिष्ठित वकीलों औऱ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल असम लेकर गया। इस प्रतिनिधिमंडल ने यहां के लोगों की दुर्दशा औऱ हालात जाने और उन्हें ढांढस बंधाया। CJP, यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक पीड़ित नहीं हो। सीजेपी सुप्रीम कोर्ट में भी यह कहने के लिए गया कि नागरिकता के विचार, अवैध अप्रवासी की परिभाषा और साथ ही लोगों की डिकेड के बारे में स्पष्ट किया जाए, जो नागरिकता के संकट से जूझ रहे हैं।

21 से 23 अगस्त, 2019 तक, हमने गुवाहाटी में तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जहाँ कानूनी विद्वानों और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों ने स्थानीय, जिला स्तर के वकीलों और पैरालीगल स्वयंसेवकों को गहराई से कौशल और प्रशिक्षण से लैस किया, जो प्रकाशन के बाद नागरिकता के जटिल मुद्दे को नेविगेट करने में मदद करते हैं। हमारी सशक्तिकरण के लिए असम में ऐसी कई और कार्यशालाओं की योजना है।

हमने उन निर्णयों के प्रमुख कारणों का पता लगाने के लिए 1000 से अधिक FT आदेशों का अध्ययन किया, जहां आवेदक को 'विदेशी' घोषित किया गया था। हम अपने पैरालीगल्स को FTs में जटिल कानूनी प्रक्रियाओं को नेविगेट करने में मदद करने के लिए एक मैनुअल विकसित कर रहे हैं।

अक्टूबर 2019 में, हमने पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज (PUCL) के साथ मिलकर, असम में नागरिकता संकट का सामना कर रहे लोगों के लिए मुंबई में एक एकजुटता बैठक का आयोजन किया। जिन लोगों ने असहायता के कारण आत्महत्या का प्रयास किया था, उन पर 'विदेशी' होने का झूठा आरोप लगाया गया था, और डिटेंशन कैंप के पीड़ितों के परिवारों ने इस बैठक में अपनी कहानियाँ साझा कीं, जिसका शीर्षक था कि भारतीय कौन है।

इस बैठक के कुछ ही समय बाद, हम डिटेंशन सेंटर के पीड़ित सुब्रत डे के पुत्र बिकी डे की मदद के

लिए साथ आए, बिकी डे ने अपनी शिक्षा को फिर से शुरू किया। पिता की मौत के बाद अपने परिवार का समर्थन करने के लिए बिकी को स्कूल छोड़ने और नौकरी की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनकी माँ और दादी कपड़े के थैलों की सिलाई करके प्रतिदिन 48 रुपये कमाती हैं!

हम वर्तमान में उन लोगों की रिहाई को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मई 2019 के आदेश के अनुसार एक निरोध शिविर में तीन साल से अधिक समय बिताया है। असम अभियान के बारे में अधिक जानकारी यहाँ मिल सकती है।

स्त्रोत: Citizens for Justice and Peace (cjp.org.in)

https://cjp.org.in/who-is-indian-can-the-nrc-decide/

https://cjp.org.in/who-is-indian-can-the-nrc-decide/

https://www.telegraphindia.com/opinion/nrc-how-a-government-and-bureaucracy-betrayed-its-people/cid/1694949

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/west-bengal-assembly-rules-out

सिटीज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) एक मानवाधिकार आंदोलन है जो सभी भारतीयों की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को कायम रखने और बचाव करने के लिए समर्पित है. हम अपने कार्य के मुख्य क्षेत्रों को अपने चार स्तम्भ कहते हैं. वे हैं:

अल्पसंख्यकों के अधिकार - धार्मिक, जातीय, लैंगिक और यौनिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ विकलांग व्यक्तियों के अधिकार.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र हमेशा स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विभिन्न विश्वास प्रणालियों, संस्कृतियों और भाषाओं की गरिमा का सम्मान करता है. हमारा मानना है कि नफरत उकसाने वाले भाषण, इस आजादी का दुरुपयोग करते हैं.

आपराधिक न्याय सुधार - CJP का मानना है कि हमारी एजेंसियां - जांच, अभियोजन पक्ष और न्यायिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और त्वरित न्याय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए और लोकतांत्रिक होने की आवश्यकता है.

बाल अधिकार - CJP शुरुआत से ही बहुलवाद और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए काम करता आ रहा है. हम किशोर न्याय सुधार और यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम करते हैं.

CJP को दिए अनुदान आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत 50% कर मुक्त हैं। दाताओं को केवल भारतीय नागरिक होना चाहिए

बैंक ट्रांसफर के लिए:
Citizens for Justice and Peace
Savings Account No: 50100035940810
Bank name: HDFC Bank
RTGS/NEFT/IFSC: HDFC0000079

किसी भी जानकारी के लिए ईमेल करें info@cjp.org.in